भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2215

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

महाराष्ट्र और बिहार में पीएम श्री स्कूल

†2215. **श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पीएम श्री योजना के अंतर्गत विशेषकर विद्यालय विकास और शिक्षा सुधारों के संबंध में क्या प्रगति हुई है;
(ख) जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और विद्यालयों और छात्रों को इससे क्या लाभ होगा;
(ग) जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है/पड़ रहा है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) बिहार में पीएम श्री के अंतर्गत अभी तक पूरे हो चुके विद्यालयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ उदाहरणपरक स्कूल के रूप में उभरना है, साथ ही आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। पीएम श्री योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य से कुल 827 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 16 स्कूल जलगांव संसदीय क्षेत्र से हैं।

पीएम श्री योजना में पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, अटल टिंकरिंग लैब्स और स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल लर्निंग टूल आधुनिक, प्रौद्योगिकी-

संचालित शिक्षा में सहायता करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

पीएम श्री योजना का उद्देश्य पीएम श्री स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता, अवसंरचना और छात्र परिणामों को बढ़ाना है। अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (एलईपी) जैसी गतिविधियाँ कक्षा 6-12 में छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी शिक्षार्थी आवश्यक योग्यता स्तरों को पूरा करते हैं। शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित नियमित शिक्षक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। योग्यता-आधारित आकलन और समग्र रिपोर्ट कार्ड की शुरूआत छात्रों का एक समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य विज्ञान और गणित क्षेत्रों के माध्यम से नवाचारी शिक्षण को प्रोत्साहित करना, प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना, तथा एसटीईएम शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए एक्सपोजर विजिट करना है।

(ग): पीएम श्री स्कूलों का चयन उन स्कूलों के समूह में से किया जाता है जो यूडाइज़+ डेटा के माध्यम से कुछ निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क को पूरा करते हैं। फिर ये स्कूल पीएम श्री स्कूल बनने के लिए पारदर्शी चुनौति पद्धति के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईसीटी लैब, विज्ञान लैब, लैब उपकरण, डिजिटल पुस्तकालय, क्लासरूम डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, एलईडी लाइटिंग, कंपोस्टिंग सुविधा आदि जैसी कमियों की पहचान करके प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत घटकवार प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है और वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मंजूरी दी जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएबी बैठक में अनुमोदित घटकों/गतिविधियों के अनुसार योजना को कार्यान्वित करते हैं।

(घ): पीएम श्री योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से कुल 804 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनमें 16 प्राथमिक विद्यालय, 284 प्रारंभिक विद्यालय, 190 माध्यमिक विद्यालय और 314 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन 804 पीएम श्री स्कूलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 639.03 करोड़ रुपये (केंद्रीय भाग और राज्य भाग) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 383.42 करोड़ रुपये केंद्रीय भाग है।

निधि जारी करने के लिए, राज्य सरकार को राज्य बजट में राज्य के हिस्से के अनुरूप प्रावधान करना होगा और योजना के एसएनए खाते के साथ सभी आईए को मैप करना होगा और उसके बाद निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजना होगा। इन अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद राज्य ने अभी तक पीएम श्री योजना के तहत निधि जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

*****